भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3011

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

3011. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की वर्तमान स्थिति क्या है और विशेषकर गंभीर जल संकट का सामना कर रहे झालावाड़ और बारां जिलों के संबंध में परियोजना अपने कार्यक्षेत्र में किस प्रकार प्रगति कर रही है;

(ख) क्या केंद्र सरकार झालावाड़-बारां जैसे क्षेत्रों में विशेषकर सिंचाई सुविधाओं, कृषि उत्पादकता और स्थानीय किसानों की आजीविका में सुधार के संदर्भ में विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस महत्वपूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन में हुए अत्यधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए परियोजना में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) मंत्रालय राजस्थान में जल संरक्षण और सिंचाई विकास के व्यापक लक्ष्यों के साथ ईआरसीपी को किस प्रकार संरेखित करने की योजना बना रहा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): चंबल नदी प्रणाली के जल के उपयोग को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के घटकों के साथ-साथ कुनो, पार्बती और कालीसिंध उप-बेसिनों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित घटकों को सम्मिलित करते हुए संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच दिनांक 05.12.2024 को एक करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ चंबल बेसिन के जल का इष्टतम उपयोग करने और दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के व्यापक हित में संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर की योजना और तैयारी के लिए समझौता किया है।

करार ज्ञापन के अनुसार, इस परियोजना से राजस्थान में 4,03,652 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 1.52 लाख हेक्टेयर मौजूदा कमान क्षेत्र का स्थिरीकरण और 2.52 हेक्टेयर (पुनर्जीवित जल के माध्यम से 0.29 लाख हेक्टेयर सहित) नए कमान क्षेत्र का विकास शामिल है। इस परियोजना से झालावाड़ जिले का 24,342 हेक्टेयर और बारां जिले का 16,850 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होना प्रस्तावित है। करार ज्ञापन में सिंचाई के अलावा, 1744.16 एमसीएम पेयजल आपूर्ति और 205.75 एमसीएम औद्योगिक जल आपूर्ति की भी परिकल्पना की गई है।

मेसर्स वाप्कोस द्वारा तैयार किए गए संशोधित पीकेसी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित कर केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

इसके अलावा, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में 2.01 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली परवन बहुउद्देशीय परियोजना को मार्च, 2022 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल किया गया है।

*****